मेहनतकशों का पैग़ाम

मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

- किसानों की लुटाई, रिलायंस की कमाई, मोदी ने करवाई 3
- अफसरों को गुलाम समझते हैं संघी 4
- पाकिस्तान से नफरत किनको है जी 4
- शिक्षा पर ताजा सरकारी कवायद - एक मूल्यांकन 5
- ईएसआई मेडिकल कॉलेजः दूसरा सत्र शुरू, तीसरे की गारंटी नहीं 8

वर्ष 29 अंक 23 फरीदाबाद, रविवार 16-31 अक्तूबर 2016 फोन : - 9999595632 2 ₹

इन्दिरा कॉलोनी स्कूल मास्टर केसः झूठ की खुलने लगी पोल

ब्लैकमेल हुए शासन, प्रशासन व पुलिस

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिनांक 16 सितम्बर को, इन्दिरा कॉलोनी स्थित सरकारी हाई स्कूल में एक षड़यन्त्र के तहत भारी हंगामा व तोड़-फ़ोड़ करके इसी स्कूल के एक वरिष्ठ अध्यापक 55 वर्षीय इन्द्र सिंह शर्मा के विरुद्ध यौन उत्पीड़न का एक झूठा मुकदमा नं. 716, महिला थाने में दर्ज कराया गया। इसमें शिकायतकर्ता और कोई नहीं 'आठवीं' जमात की एक बच्ची को बनाया गया। शिकायतकर्ता से मास्टर जी पर आरोप लगवाया गया कि उन्होंने उससे पूछा था कि उसे पीरियडस आते हैं? अपनी शिकायत में बालिका यह भी लिखती है कि इसके अतिरिक्त उन्होंने और कोई छेड़-छाड़ नहीं की।

मजदूर मोर्चा, फ़रीदाबाद ब्यूरो

8 तारीख की इस तथाकथित बात को लेकर 15 तारीख की शाम को कॉलोनी में एक बैठक हुई जिसका संयोजक इसी स्कूल में मास्टर रह चुका ओमपाल गूजर था जिसकी मास्टर इन्द्र सिंह शर्मा से पुरानी खुंदक थी। इस मीटिंग में वर्ल्ड विज़न नामक एक एनजीओ के लोग भी शामिल थे। मीटिंग में बनी योजना के अनुसार अगले दिन यानी 16 तारीख को ओमपाल की मौजूदगी एवं दिशानिर्देशन में स्कूल पर ज़ोरदार हंगामा किया गया। करीब 50-60 लोग़ों ने स्कूल पर पथराव किया और अध्यापकों की दो कारों के टायर सूए घोंप-घोंप कर पूरी तरह से बेकार कर दिये, जबकि चिकनगुनिया बुखार की वजह से मास्टर इन्द्र सिंह छुट्टी पर थे। इस हंगामे का मकसद था कि पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों पर बेजा दबाव बना कर मास्टर इन्द्र सिंह के विरुद्ध न केवल पोकसो एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया जाये बल्कि तुर्त-फुर्त उनकी गिरफ़्तारी भी कराई जाये। इस पूरे ड्रामे की कवरेज के लिये मीडिया को मैनेज स्थानीय मन्त्री विपुल गोयल का भतीजा कर रहा था।

योजना सफ़ल हुई। नाकाबिल प्रशासन तुरन्त दबाव में आ गया। अफ़सरों के हाथ-पांव फूल गये। सोचने-समझने की शक्ति एकदम विलुप्त हो गयी और नामजद एफ़आईआर दर्ज करके मास्टर जी की तलाश शुरू हो गयी। ऐसे में पकड़े जाने पर मास्टर जी सीधे जेल जाते और महीनों तक जमानत न होती। क्योंकि अदालतों के स्तर पर भी माईंड अप्लाई करने का रिवाज कम ही रह गया है। जो कहानी पुलिस बताती है उसे ही सत्यवचन मान लिया जाता है बाद में बेशक आरोप झूठे ही साबित हों। लिहाज़ा मास्टर जी ने चुपचाप गिरफ़्तार हो जाने की अपेक्षा पुलिस अधिकारियों के सामने सच्चाई लाने के शिकायत तेज़ कर दिये।

'मज़दूर मोर्चा' द्वारा की गयी जांच में पाया गया कि शिकायतकर्ता बच्ची अथवा उसके अभिभावकों ने उक्त तथाकथित छेड़छाड़ अथवा यौन उत्पीड़न के बाबत स्कूल के हेड मास्टर सुरेन्द्र सिंह यादव को कभी नहीं की। यदि उन्हें कोई शिकायत थी तो वे पहले हेडमास्टर जी से क्यों नहीं मिले? एक सप्ताह तक वे क्या खिचड़ी पकाते रहे? यदि उन्हें हेड मास्टरी जी के पास न जाकर सीधे पुलिस में ही जाना था तो भी वे एक सप्ताह तक क्या सोचते रहे? चलो, यदि निर्णय लेने में एक सप्ताह का समय लग भी गया था तो केस दर्ज कराने का यह कौनसा तरीका था कि स्कूल पर ही हल्ला बोल दिया जाय? अगर पुलिस कार्यवाही ही करानी थी तो सीधे थाने-चौकी में क्यों नहीं गये? यह तो इस नाकारा सरकार व उसके कायर प्रशासन की ऐसी-तैसी हो रही है वरना सबसे पहले तो स्कूल पर हल्ला बोलने व तोड़-फ़ोड़ करने वालों को हवालात में बंद किया जाना चाहिये था। सरकार एवं उसके प्रशासन की इन्हीं कायराना हरकतों के चलते फ़िजूल के कामों का बोझ प्रशासन पर बढ़ता जा रहा है।

'मज़दूर मोर्चा' की जांच में पाया गया कि ओमपाल गूजर इस स्कूल में गत 10 वर्षों से जमा बैठा था। पढने-पढाने से इसका कोई ताल्लुक कभी रहा नहीं तो इसे स्कूल का दफ़्तरी काम सौंप दिया जाता था। इसमें मुख्य काम था स्कूल के लिये पैसा ड्रा करके डिस्बर्स करना। इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए इसने शिकायतकर्ता की मां विमला उर्फ़ बवली को मिड डे मिल बनाने की नौकरी दे दी थी। इसके अलावा कॉलोनी की 3 और महिलाओं को भी इसी नौकरी पर लगा रखा है। जिसका पढने-पढाने से कोई ताल्लुक न हो तो वह दूसरे धंधे भी करेगा ही। लिहाज़ा मास्टर ओमपाल ने वहीं स्कूल के पास अपना प्रॉपर्टी डीलरी का एक दफ़्तर भी खोल रखा है। इन्हीं बातों का सहारा लेकर ओमपाल ने ये सारा कांड रचा।

'खुराफ़ाती दिमाग शैतान का घर' कहावत को चरितार्थ करते हुए ओमपाल ने गत वर्ष अपनी एक सहकर्मी अध्यापापिका पर डोरे डालने शुरू किये थे। मनचाहा रिसपोंस न मिलने पर उसे तत्कालीन ज़िला शिक्षाधिकारी रामकुमार पलसवाल से मिलीभगत करके सस्पेंड करा दिया। यह रामकुमार पलसवाल ओमपाल की जेब में रहता, बताया क्योंकि वह उसकी रोज़ाना दारू-मुर्गे की सेवा करता है। उस समय पूरे स्टाफ़ खासकर इन्द्र सिंह ने उस अध्यापिका के पक्ष में बोल कर उसे तो बहाल करा दिया परन्तु ओमपाल को अपना दुश्मन बना लिया। कुछ दिन बाद जब वही अध्यापिका स्कूल से अपने घर जा रही थी तो ओमपाल ने उसे अपनी कार में लिफ़्ट देकर छेड़छाड़ कर दी। इसकी शिकायत पर विभागीय जांच बैठी और जांच उपरांत ओमपाल का तबादला मेवात का कर दिया गया जहां वह कभी गया नहीं। स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर की सिफ़ारिस से अपना तबादला वापस इसी ज़िले के वजीरपुर में कराने के बाद अपनी तैनाती एनआईटी 5 नं. स्थित बाल सुधार गृह में करा ली। वहां कोई पूछने वाला नहीं जाओ न जाओ। ऐसे में उसके पास षड़यन्त्र रचने का पूरा समय रहता है।

वर्ल्ड विज़न एनजीओ वाले भी इन्द्र सिंह से परेशान रहते थे क्योंकि वे स्कूल टाइम में इस एनजीओ की गतिविधियों का विरोध करते थे। इस एनजीओ वाले जब चाहे स्कूल एवं इन्द्र सिंह की कक्षा में आ घुसते थे और बच्चों, अधिकतर बच्चियों को बाहर घुमाने-कभी दिल्ली, कभी आगरा आदि ले जाते थे। ओमपाल को इस बात का पता था लिहाज़ा उसने अपने साथ इस एनजीओ को भी जोड़ लिया। मज़ेदार बात यह है कि शिकायतकर्ता बच्ची के हक में झूठी गवाही देने वाली भी वही 8-10 बच्चियां तैयार की गयी हैं जो इस एनजीओ से जुड़ी हैं। इस एनजीओ ने अपनी एजेंट के तौर पर इसी कॉलोनी की रेशमा नाम की एक महिला को भी तैनात कर रखा है जो गवाह बनी बच्चियों को बहला पुचकार कर थामे हुए है।

स्कूल के तमाम स्टाफ़, शिक्षा विभाग के एक पूर्व अधिकारी ने भी इन्द्र सिंह के हक में खुल कर बयान दर्ज कराये हैं। इन सबके आधार पर अब पुलिस अधिकारियों को भी समझ आने लगा है कि उनसे गलती कहां हुई, आगे और कोई गलती न होने दी जाय। मौजूदा अधिकारियों पर भी ओमपाल हावी रहता है। वह इन सब को तबादले का भय दिखा कर ब्लैकमेल करता रहता है। इसी दबाव के चलते यह सुधार गृह में ड्यूटी लगवा कर छुट्टा घूमता फ़िर रहा है।

यमुना पुल के नाम पर कब तक बहलायेंगे कृष्णपाल

फ़रीदाबाद (म.मो.) धारातल पर कोई काम करना तो स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मन्त्री कृष्णपाल गूजर के बस का कुछ है नहीं, इसलिये नारियल फ़ोड़ने, थाने-चौकियों में तैनाती कराने व लूट-मार के धंधों में ही व्यस्त रहने वाले मन्त्री जी ने जनता को बहलाये रखने के लिये यमुना पुल का एक झुनझुना पकड़ रखा है। गत ढाई वर्ष से वे इसे हर दूसरे-तीसरे महीने बजाते रहते हैं।

बीते पखवाड़े कृष्णपाल ने फ़िर स्थानीय अखबारों में इसी पुल का राग छेड़ते हुए जनता को यह बताया कि वे मुख्यमंत्री खट्टर को लेकर लखनऊ गये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने। उनके साथ अफ़सरों व लगुए-भगुओं का एक लम्बा-चौड़ा काफ़िला भी था वहां जाकर इन लोग़ों ने बड़े 'प्रयास' करके अखिलेश यादव को मनाया और उनसे उक्त पुल बनाने में उनके सहयोग का सहमति पत्र हासिल किया। दरअसल इस पुल के लिये बनने वाली 19 किलोमीटर लम्बी सड़क हरियाणा में बनेगी जिसका अधिग्रहण 150 करोड़ की लागत से हरियाणा सरकार करेगी। यमुना पर प्रस्तावित पुल बनने के बाद इस सड़क को यमुना एक्स्प्रेस वे से जोड़ने के लिये 5 किलोमीटर का भू-भाग उत्तर प्रदेश में पड़ता है जिसके अधिग्रहण का भार उत्तर प्रदेश सरकार ने वहन करना स्वीकार कर लिया है। वैसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट पर अपनी असहमति जताने का जिक्र भी कभी सुनने में नहीं आया। जब उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं इसके लिये तैयार थी तो कृष्णपाल द्वारा इस नौटंकी की जरूरत क्या थी?

इतनी बड़ी जिस 'उपलब्धि' को लेकर मन्त्री कृष्णपाल अपनी पीठ खुद ही ठोक रहे हैं, उस पर सवाल उठता है कि 15 अगस्त 2014 को जब इन मन्त्री जी ने केन्द्रीय सड़क मन्त्री नितिन गडकरी से इस पुल का शिलान्यास कराया था तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार से कोई बात-चीत नहीं की थी, क्या उनसे सहमति के बिना ही यहां शिलान्यास का इतना बड़ा ड्रामा रच दिया था। पाठक याद करें कि उस वक्त शिलान्यास के इस ड्रामे पर सैंकड़ों बसों व ट्रैक्टर ट्रालियों में लाद कर जनता को लाया गया था। उस वक्त सिर पर खड़े हरियाणा विधानसभा के चुनावों के मद्दे-नज़र गडकरी ने 300 करोड़ की लागत से इस पुल को 2 वर्ष में चालू कर देने का झूठा वायदा किया था।

अब इस पुल की लागत 400 करोड़ बताई जा रही है जबकि दोनों राज्य सरकारों द्वारा भूमि अधिग्रहण का खर्च अलग से होगा। झूठे और बेइमानों की सरकार कहने को तो यह कह रही है कि पुल निर्माण का सारा खर्च केन्द्र सरकार वहन करेगी और आगामी डेढ वर्ष में पुल चालू हो जायेगा। परन्तु जिस सरकार ने सारी सड़कें बेच खाई हों और जगह-जगह टोल नाके लगा कर अवैध वसूली को कानूनी जामा पहना दिया हो, जो कृष्णपाल गूजर सांसद का चुनाव लड़ते वक्त टोल टैक्स को जजिया बताने के बावजूद टोल की वसूली को न केवल जारी रखे हैं बल्कि उसमें लगातार वृद्धि भी हो रही है, उस सरकार पर कैसे कोई भरोसा कर सकता है कि उक्त प्रस्तावित पुल टोल-मुक्त होगा। रही बात डेढ साल में पुल चालू करने की तो यकीन नहीं होता। यकीन हो भी कैसे जब फ़रीदाबाद शहर के बीचों -बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर ठेका देने के 6 वर्ष बाद भी काम पूरा नहीं हो सका तो यमुना जैसी बड़ी नदी पर डेढ साल में पुल बन कैसे सकता है, जबकि अभी तक तो किसी कम्पनी को काम का ठेका तक भी नहीं दिया गया है और न ही सम्बन्धित ज़मीनों का अधिग्रहण ही हो पाया है। वैसे भी इन प्रमाणित झूठों की बात पर कोई भी समझदार यकीन कैसे कर सकता है। हां आगामी संसदीय चुनाव से थोड़ा पहले पुल निर्माण सम्बन्धी कुछ ड्रामेबाज़ी व आश्वासनबाज़ी जरूर हो सकती है।

सुधी पाठक ज़रा याद करें कि गत 26 महीनों में मंत्री गूजर हर दूसरे-तीसरे महीने मीडिया में पुल का चर्चा जरूर करते रहे हैं। कभी डीपीआर बनने की बात तो कभी सड़क के लिये भूमि अधिग्रहण की बात तो कभी इसके लिये उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठन की बात तो कभी किसानों द्वारा अपनी ज़मीनों को अधिग्रहीत नहीं होने देने की बात, आदि-आदि।

कुल मिलाकर गूजर एवं इनकी संघी सरकार जनता को झूठे सपने बेचने के और कुछ नहीं कर रही है। ये सारी बातें 'मज़दूर मार्चा' के सितम्बर 2014 अंक में विस्तारपूर्वक प्रकाशित की जा चुकी हैं। विदित है कि इस पुल के न होने से नौयडा आदि की ओर जाने वाले हज़ारों वहनों को दिल्ली से होकर गुजरना पड़ता है जिससे समय की बर्बादी के साथ-साथ पैट्रोल के रूप में धन की बर्बादी तो होती ही है, वायु प्रदूषण में बढोत्तरी का 'बोनस' अलग से मिला है।

स्मार्ट सिटी कैसे बनेः सीखने लंदन गयी निगमायुक्त

फ़रीदाबाद (म.मो.) स्मार्ट सिटी का ड्रामा अब राष्ट्रीय स्तर से ऊपर उठ कर अन्तर्राष्ट्रीय हो गया है। भारत सरकार के शहरी विकास मन्त्रालय ने फ़रीदाबाद व चंडीगढ सहित 9 शहरों के निगमायुक्तों को 3 अक्तूबर को लंदन के लिये रवाना कर दिया। ये आईएएस अधिकारी वहां जाकर अंग्रेजों से 'सिखेंगे' कि वे अपने शहरों को उनके शहरों जैसा स्मार्ट कैसे बनायें? करीब 200 साल की अपनी हकूमत के दौरान उन्होंने शहरों को स्मार्ट एवं साफ़-सुथरा रखने का जो पाठ पढ़ाया था उसे बीते 70 सालों में भुला देने के बाद अब फ़िर उनसे ट्यूशन पढ़ने की जरूरत आन पड़ी लगती है। इससे यह स्वत: सिद्ध है कि इस देश के शासक-प्रशासक कितने नालायक एवं नाकाबिल हैं। इसी बात को सिद्ध करने के लिये करीब 2-3 वर्ष पूर्व शिमला शहर की दुर्दशा सुधारने के लिये भी लंदन शहर के मेयर से सम्पर्क किया गया था।

शिमला हो या मुंबई कलकत्ता या नई दिल्ली, जब तक अंग्रेज रहे, इन शहरों में कोई अनियमितता नहीं होने दी गयी। जो नियम-कानून बना दिये जाते थे वे पूरी सख्ती से स्वत: लागू हो जाते थे। उस वक्त किसी तोड़-फ़ोड़ दस्ते की जरूरत नहीं पड़ती थी। सब लोग जानते व समझते थे कि कानून-कायदे केवल मानने के लिये होते हैं न कि तोड़ने के लिये। लिहाज़ा उस वक्त न तो सीवर ओवरफ्लो होते थे न बरसाती पानी से सड़कें नहर का रूप ले पाती थीं और न ही सड़कों पर गड्ढे हो सकते थे। उक्त तीनों में से यदि कहीं भी कोई काम हो गया तो सम्बन्धित अधिकारी की खैर नहीं हो सकती थी। उस वक्त निकम्मे एवं भ्रष्ट अधिकारियों को सरकारी कहर से बचाने के लिये बेईमान व चोर उच्चके राजनेता भी नहीं हुआ करते थे। बस इसी दहशत के चलते किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह किसी कानून-कायदे को ज़रा भी टूटने दे।

समझ नहीं आता कि अंग्रेज बेचारे, हमारे इन अफ़सरों को कैसे समझा पायेंगे कि अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण केसे रोका जाय? सरकारी अफ़सरों द्वारा की जाने वाली हरामखोरी, चोरी व रिश्वतखोरी को कैसे रोका जाये? ढाई छटांक पानी बरसा नहीं कि शहर की तमाम सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, सारा शहर कीचड़ से भर जाता है, पहले से ही उफ़नते सीवरों का सड़ा सीवेज सड़कों -गलियों में आ जमता है। 10-20 घंटों के लिये बिजली गुल हो जाती है। सड़क यातायात दौड़ने की बजाय रेंगने लगता है। यह सब क्या है? हरामखोरी व रिश्वतखोरी के अलावा कुछ भी नहीं। ऐसे में लंदन वाले क्या मंत्र बतायेंगे, जो यह सब ठीक हो जाये, समझ से परे है।

एक चर्चा यह भी है कि यदि लंदन वाने निगमायुक्त को बहकावे में आ गये तो विकास के नाम पर फ़रीदाबाद नगर निगम को 800 करोड़ रुपये मिल जायेंगे। फ़िलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि बेईमानी व हरामखोरी द्वारा कंगले हो चुके इस निगम को इतनी बड़ी रकम देगा कौन-भारत सरकार या लंदन सरकार? अंग्रेज बड़ी सयानी व चतुर कौम है। वह बहकावे में आकर किसी को कुछ नहीं दिया करती, हां अपने किसी राष्ट्रीय हित एवं स्वार्थ को साधने के लिये भीख का कोई टुकड़ा भारत सरकार को दे देवे तो अलग बात है।

वैसे भारत सरकार द्वारा भीख में दिये जवाहर लाल नेहरू अर्बन मिशन, व यमुना एक्शन प्लान के नाम पर सैंकड़ों, हज़ारों करोड़ रुपये यह निगम पहले ही निगल चुका है। इसके अलावा अपनी खुद की जायदादें बेच खाने व गुड़गांव नगर निगम से सैंकड़ों करोड़ के कभी न लौटाने वाले कर्जे अलग से। इन सबके बावजूद शहर भयंकर दुर्दशा का शिकार है और निगम के पास कर्मचारियों को देने के लिये वेतन तक नहीं।

शेष पेज दो पर